खंडों पर टिप्पण

आय-कर

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित खंड 2 वे दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए हैं, जिन पर आय-कर निर्धारण वर्ष 2008-2009 के लिए कर से प्रभार्य आय पर उद्गृहीत किया जाना है। इसके अतिरिक्त, यह खंड उन दरों को, जिन पर वित्तीय वर्ष 2008-2009 के दौरान ऐसी आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है, जो आय-कर अधिनियम के अधीन कटौती के अधीन रहते हुए हैं और उन दरों को भी, जिन पर वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए “अग्रिम कर” का संदाय किया जाना है, “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में कर का परिकलन और प्रभारण किया जाना है, अधिकथित करता है।

निर्धारण वर्ष 2008-2009 के लिए आय-कर की दरें

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 1, आय-कर की वे दरें विनिर्दिष्ट करता है जिन पर आय निर्धारण वर्ष 2008-2009 के लिए कर के दायित्वाधीन है। ये वे दरें हैं, जो वित्त अधिनियम, 2007 की पहली अनुसूची के भाग 3 में, वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान “वेतन” से स्रोत पर कर की कटौती करने, “अग्रिम कर” की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर परिकलित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के दौरान “वेतन” से भिन्न आय से स्रोत पर कर की कटौती की दरें

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 2, वे दरें विनिर्दिष्ट करता है, जिन पर, “वेतन” से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2008-2009 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती की जानी है। उस दर को जिस पर धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आप से कर की कटौती की जाती है, दस प्रतिशत से बढ़ाकर पंद्रह प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी से भिन्न, भारत में निवासी किसी व्यक्ति की दशा में, उस दर को, जिस पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की प्रतिभूति पर संदेय ब्याज के रूप में आय से कर की कटौती की जानी है, दस प्रतिशत पर विनिर्दिष्ट किया गया है। शेष मामलों में वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए दरें वही होंगी, जो वित्त अधिनियम, 2007 की पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट हैं।

इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम में,—

(i) प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति-संगम और व्यक्ति-निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां आय अथवा ऐसी कुल आय का संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है, और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, जो दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(iii) प्रत्येक फर्म और देशी कंपनी की दशा में, जहां आय या ऐसी कुल आय का संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(iv) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां आय या ऐसी कुल आय का संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।

किसी सहकारी सोसाइटी या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

सभी मामलों में, आय-कर और अधिभार के दो प्रतिशत की दर से (“आय-कर पर शिक्षा उपकर” नामक अतिरिक्त अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए उद्गृहीत किया जाता रहेगा, जिससे कि सार्वत्रिक गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके।

सभी मामलों में आय-कर और अधिभार के (जिसके अंतर्गत शिक्षा उपकर नहीं है) एक प्रतिशत की दर से “आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर” नामक अतिरिक्त अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए उद्गृहीत किया जाता रहेगा, जिससे कि सार्वत्रिक गुणवत्ता की माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के दौरान “वेतन” से स्रोत पर कर की कटौती करने, “अग्रिम कर” की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 3, वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए वे दरें, जिन पर “वेतन” से स्रोत पर आय-कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और वे दरें भी, जिन पर “अग्रिम कर” का संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में आय-कर परिकलित या प्रभारित किया जाना है, विनिर्दिष्ट करता है।

इस भाग का पैरा क प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब या प्रत्येक व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे भाग 3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है, आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। ऐसे मामलों में आय-कर की दरें निम्न प्रकार होंगी—

1,50,000 रुपए तक	कुछ नहीं
1,50,001 रुपए से 3,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
5,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है, कुल आय पर आय-कर की दरें निम्न प्रकार होंगी,—

1,80,000 रुपए तक	कुछ नहीं
1,80,001 रुपए से 3,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
5,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष की या अधिक की आयु का है, कुल आय पर आय-कर की दरें निम्न प्रकार होंगी,—

2,25,000 रुपए तक	कुछ नहीं
2,25,001 रुपए से 3,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
3,00,000 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
5,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

पैरा क यह और उपबंध करता है कि संगणित आय-कर की रकम में से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या नहीं, जिसकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटाकर आए आय-कर को ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तथापि, दस लाख रुपए से अधिक कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय आय-कर और अधिभार की कुल रकम, दस लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो दस लाख रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

पैरा क यह भी उपबंध करता है कि संगणित आय-कर की रकम में, आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक

व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

पैरा क में उद्गृहीत अधिभार की दरों में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं है।

इस भाग का पैरा ख प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। ऐसी दशाओं में, आय-कर की दरें वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2008-2009 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं। कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

इस भाग का पैरा ग प्रत्येक फर्म की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। ऐसी दशाओं में, आय-कर की दरें वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2008-2009 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, संगणित आय-कर की रकम में ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर पर परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

इस भाग का पैरा घ प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। ऐसी दशाओं में, कर की दरें वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2008-2009 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं। कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

इस भाग का पैरा ङ कंपनियों की दशा में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, कर की दरें वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2008-2009 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं। पैरा ङ यह और उपबंध करता है कि देशी कंपनी से भिन्न कंपनियों की दशा में, कर की दरें वही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2008-2009 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं।

पैरा ञ कंपनियों की दशा में अधिभार की दर का भी उपबंध करता है। संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर पर परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर पर परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

ऐसे मामलों में सीमांत राहत दी जाएगी, जिससे एक करोड़ रुपए से अधिक कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, भी सीमांत राहत दी जाएगी।

आय-कर अधिनियम की धारा 115बक के अधीन कर से प्रभार्य किन्हीं अनुषंगी फायदों की बाबत संदेय कर में निम्नानुसार अधिभार बढ़ा दिया जाएगा:—

(क) प्रत्येक व्यक्ति-संगम और व्यक्ति निकाय की दशा में, जहां अनुषंगी फायदे दस लाख रुपए से अधिक है, दस प्रतिशत की दर से;

(ख) प्रत्येक फर्म, कृत्रिम विधिक व्यक्ति और देशी कंपनी की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से।

“आय-कर पर शिक्षा उपकर” नामक अतिरिक्त अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, आय-कर और अधिभार के दो प्रतिशत की दर पर, उद्गृहीत किया जाता रहेगा। सभी दशाओं में “माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर” नामक अतिरिक्त अधिभार,

संघ के प्रयोजनों के लिए, आय-कर और अधिभार (जिसके अंतर्गत शिक्षा उपकर नहीं है) के एक प्रतिशत की दर पर, उद्गृहीत किया जाता रहेगा।

खंड 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है जो परिभाषाओं से संबंधित है।

यह खंड धारा 2 के खंड (1क) के स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् एक नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी नर्सरी में उगाए गए पौधों या पौध से व्युत्पन्न कोई आय कृषि आय समझी जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा का खंड (15) “पूर्त प्रयोजन” को इस प्रकार परिभाषित करता है जिससे कि उसमें गरीबों को सहायता, शिक्षा, चिकित्सा सहायता और सामान्य लोक उपयोग के किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करने को सम्मिलित किया जा सके।

उक्त खंड में एक परंतुक अंतःस्थापित करके उसका संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे “सामान्य लोक उपयोग के किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करने” से निम्नलिखित को अपवर्जित किया जा सके,—

(i) व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप; या

(ii) उपकर या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप,

चाहे ऐसे किसी क्रियाकलाप से आय के उपयोग या उपयोजन या प्रतिधारण की कोई भी प्रकृति हो।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 4—आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है जो ऐसी आय से संबंधित है जो कुल आय का भाग नहीं है। धारा 10 में नया खंड (26ककक) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी कोई आय जो “सिक्किमी” व्यक्ति को सिक्किम राज्य में किसी स्रोत से या लाभांश अथवा प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में प्रोद्भूत या उद्भूत होती है, ऐसे व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

“सिक्किमी” पद को सिक्किम प्रजा विनियम, 1961 उसके अधीन बनाए गए नियमों और इस संबंध में जारी किए गए सुसंगत सरकारी आदेशों के अनुसरण में उक्त खंड में विनिर्दिष्ट किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 1990 से, भूतलक्षी रूप से, प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1990-91 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 4, उक्त धारा के खंड (29क) का और संशोधन के लिए है, जो उक्त खंड के उपखंड (क) से उपखंड (छ) में विनिर्दिष्ट कतिपय वस्तु बोर्डों और निर्यात विकास प्राधिकारियों की किसी आय को छूट के लिए उपबंध करता है। यह प्रस्ताव है कि कयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अधीन स्थापित कयर बोर्ड से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली किसी आय की बाबत छूट का उपबंध करने के लिए एक नया उपखंड अंतःस्थापित किया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 4, उक्त धारा में एक नया खंड (43) अंतःस्थापित करने के लिए भी है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यक्ति को धारा 47 के खंड (xvi) में निर्दिष्ट प्रतिवर्ती बंधक के संव्यवहार में उधार के रूप में, चाहे एकमुश्त या किस्तों में, प्राप्त कोई आय कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 5—आय-कर अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है जो वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (ii) किसी ऐसी राशि के एक सही एक बटा चार गुणा के बराबर किसी रकम, जो किसी ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान संगम को, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना है या किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए संदत्त की गई हो की कटौती अनुज्ञात करता है। उपबंध ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित और अधिसूचित किए जाने की अपेक्षा भी करता है।

इसके अतिरिक्त उक्त धारा की उपधारा (2कख) वैज्ञानिक अनुसंधान पर उपगत ऐसे व्यय के, जो अनुमोदित आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा पर किसी भूमि या भवन की लागत के प्रकार का व्यय न हो, एक सही एक बटा दो के बराबर राशि की कटौती अनुज्ञात करती है। यह कटौती विनिर्दिष्ट कारबार में लगी हुई कंपनी को उपलब्ध है।

यह संशोधन उक्त धारा की उपधारा (1) में खंड (ii) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि किसी कंपनी को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संदत्त किसी राशि के एक सही एक बटा चार गुणा के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जा सके, परंतु ऐसी कंपनी—

(अ) भारत में रजिस्ट्रीकृत है ;

(आ) उसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास करना है ;

(इ) उसे इस खंड के प्रयोजनों के लिए तत्समय विहित रीति में विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है ; और

(ई) ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती है जो विहित की जाएं।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा की उपधारा (2कख) में खंड (6) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ii) के उपखंड (ग) के अधीन अनुमोदित किसी कंपनी को उपधारा (2कख) के खंड (1) में निर्दिष्ट ऐसे व्यय की बाबत, जो 31 मार्च, 2008 के पश्चात् उपगत किया गया है, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में तदनुसार लागू होंगे।

खंड 6—आय-कर अधिनियम की धारा 35घ का संशोधन करने के लिए है जो कतिपय प्रारंभिक व्ययों के अपाकरण से संबंधित है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन, कारबार आय की संगणना करने में कतिपय विनिर्दिष्ट प्रारंभिक व्ययों के लिए कटौती अनुज्ञात है। यह कटौती, पांच क्रमवर्ती पूर्ववर्षों के लिए ऐसे व्यय के एक बटा पांच के बराबर रकम की अनुज्ञात है। प्रारंभिक व्यय या तो कारबार के प्रारंभ के पूर्व की अवधि या उसके पश्चात् की अवधि से संबंधित है। तथापि, यदि प्रारंभिक व्यय कारबार के प्रारंभ के पश्चात् की अवधि से संबंधित है तो ऐसे व्यय तभी अनुज्ञात हैं यदि वे औद्योगिक उपक्रम के विस्तार या नया औद्योगिक एकक स्थापित करने के संबंध में हैं।

प्रस्तावित संशोधन “औद्योगिक उपक्रम” शब्दों के स्थान पर, “उपक्रम” शब्द और “औद्योगिक एकक” शब्द के स्थान पर, “एकक” शब्द उक्त धारा में जहां कहीं वे आते हैं, रखने के लिए है। इसका आशय सभी सेक्टरों के विस्तार के लिए विनिर्दिष्ट प्रारंभ के पश्चात् प्रारंभिक व्ययों के अपाकरण के फायदे के लिए उपबंध करने का था।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 7—आय-कर अधिनियम की धारा 36 का संशोधन करने के लिए है जो कारबार की आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए अन्य कटौतियों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में नया खंड (xv) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारित द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान अपने कारबार के अनुक्रम में किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों की बाबत पूर्ववर्ष के दौरान संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार कर के बराबर रकम कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी यदि ऐसे कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों से उद्भूत होने वाली आय “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन संगणित आय में सम्मिलित की गई है।

यह उपबंध करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “प्रतिभूति संव्यवहार कर” और “कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार” पदों के वही अर्थ होंगे, जो वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 में हैं।

उक्त खंड 7 उक्त धारा की उपधारा (1) में नया खंड (xvi) अंतःस्थापित करने के लिए भी है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारित द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान अपने कारबार के अनुक्रम में किए गए कराधेय वस्तु संव्यवहारों की बाबत पूर्ववर्ष के दौरान संदत्त वस्तु संव्यवहार कर के बराबर रकम, कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी यदि कराधेय वस्तु संव्यवहारों से उद्भूत होने वाली आय “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन संगणित आय में सम्मिलित की गई है।

यह उपबंध करने के लिए स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “वस्तु संव्यवहार कर” और “कराधेय वस्तु संव्यवहार” पदों के वही अर्थ होंगे जो वित्त अधिनियम, 2008 के अध्याय 7 में हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 8— धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (ix) का लोप करने के लिए है जिसमें यह उपबंध है कि प्रतिभूति संव्यवहार कर के सम्बन्ध में संदत्त कोई राशि “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 9—आय-कर अधिनियम की धारा 40क का संशोधन करने के लिए है जो ऐसे व्यय के संदाय से संबंधित है जो कतिपय दशाओं में कटौती योग्य नहीं है।

उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन ऐसे उपगत व्यय को, जिसकी बाबत बीस हजार रुपए से अधिक की राशि का कोई संदाय बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी अन्य रीति से किया जाता है, कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया गया है। धारा 40क की उपधारा (3) के खंड (ख) में भी किसी संदाय को कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ समझे जाने के लिए उपबंध है, यदि संदाय किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में पाने वाले के खाते में देय चेक से या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी रीति में 20,000 रुपए से अनधिक की राशि के लिए किया जाता है।

संशोधन उक्त उपधारा (3) को उपधारा (3) और उपधारा (3क) से प्रतिस्थापित करने के लिए है। प्रस्तावित उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि जहां निर्धारित किसी दिन बीस हजार रुपए के पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न बीस हजार रुपए से अधिक का व्यय करता है वहां ऐसे व्यय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

प्रस्तावित उपधारा (3क) यह उपबंध करती है कि जहां किसी व्यय के लिए निर्धारित द्वारा उपगत किसी दायित्व की बाबत कोई मोक किसी वर्ष में निर्धारण में अनुज्ञात किया गया है और तत्पश्चात् किसी पूर्ववर्ष के दौरान (जिसे इसमें इसके पश्चात् पश्चात्वर्ती वर्ष कहा गया है) निर्धारित उसकी बाबत संदाय बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक से या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी अन्य रीति में करता है वहां इस प्रकार किए गए संदाय कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे तथा तदनुसार यदि किसी दिन में किसी व्यक्ति को किया गया संदाय या कुल संदाय बीस हजार रुपए से अधिक होता है तो पश्चात्वर्ती वर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभाय होगी।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां किसी व्यक्ति को किसी दिन में बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी रीति में किया गया संदाय या कुल संदाय बीस हजार रुपए से अधिक हो जाता है वहां ऐसे मामलों में और ऐसी परिस्थितियों के अधीन जो विहित की जाएं, उपलब्ध बैंककारी सुविधाओं की प्रकृति और सीमा कारबार की समीचीनता तथा अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोई भी अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और कोई अन्य संदाय उपधारा (3) और उपधारा (3क) के अधीन कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ नहीं समझे जाएंगे।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 10—आय-कर अधिनियम की धारा 43 का संशोधन करने के लिए है जो कारबार या वृत्ति के लाभों या अभिलाषों से होने वाली आय से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषा से संबंधित है।

उक्त धारा के खंड (6) का उपखंड (ख) यह उपबंध करता है कि पूर्व वर्ष से पहले अर्जित आस्तियों की दशा में अवलिखित मूल्य से अभिप्रेत है निर्धारिती की वह वास्तविक लागत जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 के अधीन या उस अधिनियम द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन या उस समय जब कि भारतीय आय-कर अधिनियम, 1886 प्रवृत्त था, जारी किए गए किन्हीं कार्यपालिक आदेशों के अधीन उसको सभी वस्तुतः अनुज्ञात किए गए अवक्षयण को उसमें से घटाकर आय।

उक्त खंड (6) में स्पष्टीकरण 6 अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारिती विचाराधीन निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष या पूर्व वर्ष से पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आय-कर के प्रयोजनों के लिए अपनी कुल आय की संगणना करने के लिए अपेक्षित नहीं था, वहां,-

(क) किसी आस्ति के वास्तविक मूल्य को लेखाबहियों में ऐसी आस्ति के पुनर्मूल्यांकन के कारण, यदि कोई हो, मान्य रकम से समायोजित किया जाएगा ;

(ख) विचाराधीन निर्धारण वर्ष से सुसंगत ऐसे पूर्ववर्ष से पूर्ववर्ती वर्षों की बाबत निर्धारिती की लेखाबहियों में दी गई ऐसी आस्तियों के संबंध में अवक्षयण की कुल रकम को उक्त धारा के खंड (6) के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम की अधीन वास्तव में अनुज्ञात किया गया अवक्षयण समझा जाएगा ;

(ग) उपरोक्तानुसार वास्तव में अनुज्ञात अवक्षयण की रकम से समायोजित किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से भूतल क्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा पचातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 11—आय-कर अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने के लिए है जो अंतरण न समझे जाने वाले संव्यवहारों से संबंधित है।

एक नया खंड (xक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 115कग की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट बंधपत्रों का किसी कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों में परिवर्तन के रूप में किसी अंतरण को अंतरण नहीं माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, उक्त धारा में एक नया खंड (xvi) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अधीन प्रतिवर्ती बंधक के संव्यवहार में किसी पूंजी आस्ति के किसी अंतरण को सूची में जोड़ा जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 12—आय-कर अधिनियम की धारा 49 का संशोधन करने के लिए है जो अर्जन के कतिपय ढंगों के संबंध में लागत से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2क) यह उपबंध करती है कि जहां पूंजी आस्ति, जो किसी कंपनी का शेयर या डिबेंचर है, धारा 47 के खंड (x) में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो गई है, वहां निर्धारिती को आस्ति के अर्जन की लागत, ऐसे डिबेंचर, डिबेंचर स्टाक या निक्षेप प्रमाणपत्र की, जिसकी बाबत ऐसी आस्ति निर्धारिती द्वारा अर्जित की गई है, लागत का भाग समझी जाएगी।

उक्त उपधारा का यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है कि जहां पूंजी आस्ति, जो किसी कंपनी का शेयर या डिबेंचर है, धारा 47 के खंड (x) या खंड (xक) में निर्दिष्ट अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो गई है, वहां निर्धारिती को आस्ति के अर्जन की लागत, ऐसे डिबेंचर, डिबेंचर स्टाक, बंधपत्र या निक्षेप प्रमाणपत्र की, जिसकी बाबत ऐसी आस्ति निर्धारिती द्वारा अर्जित की गई है, लागत का भाग समझी जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 13—आय-कर अधिनियम की धारा 80ग का संशोधन करने के लिए है जो जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अभिदाय, कतिपय साधारण शेयरों या डिबेंचरों आदि में अभिदान के संबंध में कटौती से संबंधित है। यह धारा किसी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब के संबंध में, कतिपय बचत लिखतों में विनिधान करने के लिए या ट्यूशन फीस संबंधी व्यय उपगत करने और आवासिक ऋण का प्रतिदाय करने के लिए एक लाख रुपए तक की कटौती का उपबंध करता है।

उक्त धारा की उपधारा (2) में पात्र बचत लिखतों की परिधि का विस्तार करने के लिए नए खंड (xxiii) और खंड (xxiv) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 के अधीन किसी खाते में या डाकघर सावधि बचत नियम, 1981 के अधीन किसी खाते में पांच वर्षीय सावधि जमा के रूप में संदत्त या निक्षिप्त कोई राशि भी कर फायदों के लिए पात्र होगी।

इसके अतिरिक्त, एक नई उपधारा (6क) अंतःस्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई रकम, जिसके अंतर्गत उस पर प्रोद्भूत ब्याज भी है, निर्धारिती द्वारा उसके निक्षेप की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व ऐसे खाते से निकाली जाती है तो इस प्रकार निकाली गई रकम ऐसे पूर्ववर्ष में, जिसमें रकम निकाली जाती है, निर्धारिती की आय समझी जाएगी और उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष में कर के लिए दायी होगी। तथापि, यदि ऐसी रकम, ऐसे निर्धारिती की मृत्यु पर निर्धारिती के नामनिर्देशिती या विधिक वारिस द्वारा प्राप्त की जाती है तो, यथास्थिति, ऐसे नामनिर्देशिती या विधिक वारिस द्वारा इस प्रकार प्राप्त रकम कर के लिए दायी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, तथापि ऐसी रकम में सम्मिलित ब्याज जो किसी पूर्ववर्ती वर्ष में निर्धारिती की आय में सम्मिलित नहीं की गई है। यदि ऐसी रकम में सम्मिलित ब्याज को उस पूर्ववर्ष से पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष या वर्षों के लिए, जिसमें रकम निकाली जाती है, निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने के लिए, विचार में लिया गया है तो ऐसा ब्याज पुनः कर के लिए दायी नहीं होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 14—आय-कर अधिनियम की धारा 80घ का प्रतिस्थापन करने के लिए है जो चिकित्सा बीमा प्रीमियम की बाबत कटौती के संबंध में है।

उक्त धारा ऐसे निर्धारिती से, जो व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, और जो विनिर्दिष्ट राशि का संदाय,—

(क) जहां निर्धारिती व्यक्ति है, वहां निर्धारिती के स्वास्थ्य का या उसकी पत्नी या पति, निर्धारिती के आश्रित माता-पिता या आश्रित बालकों के स्वास्थ्य का,

(ख) जहां निर्धारिती हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, वहां उसके कुटुंब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य का,

बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए चेक से भिन्न किसी ढंग से करता है, पंद्रह हजार रुपए तक की कटौती का उपबंध करती है।

उक्त धारा यह भी उपबंध करती है कि यदि बीमाकृत व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है तो कटौती बीस हजार रुपए तक की उपलब्ध होगी।

व्यष्टिक निर्धारितियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कि वे अपने माता-पिता की, अपना बीमा कराने में उनके प्रयासों में सहायता करें, उक्त धारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसे व्यष्टिक निर्धारिती के लिए पंद्रह हजार रुपए तक की अतिरिक्त कटौती का उपबंध किया जा सके जो अपने माता-पिता के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए नकद से भिन्न किसी ढंग से विनिर्दिष्ट राशि का संदाय करता है। निर्धारिती पर माता-पिता के आश्रित होने की विद्यमान शर्त को हटाने का प्रस्ताव है। यह कटौती किसी व्यष्टिक निर्धारिती को अपने स्वयं के, अपने पति या अपनी पत्नी और आश्रित बालकों के बीमा कराने पर उपलब्ध पंद्रह हजार रुपए तक की विद्यमान कटौती के अतिरिक्त होगी।

यह भी प्रस्ताव है कि यदि व्यष्टिक निर्धारिती के माता-पिता में से कोई वरिष्ठ नागरिक है और जिसका बीमा कराया गया है, उपलब्ध कटौती बीस हजार रुपए तक की होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 15—आय-कर अधिनियम की धारा 80इअ का संशोधन करने के लिए है जो अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (9) खनिज तेलों के वाणिज्यिक उत्पादन या परिष्करण से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती का उपबंध करती है । अधिनियम की अन्य धाराओं से भिन्न "खनिज तेल" पद के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नहीं है ।

इस उपधारा के अधीन कटौती किसी उपक्रम को सात क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए, उपलब्ध है जिसके अंतर्गत आरंभिक निर्धारण वर्ष भी है,—

(i) जिसमें उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के अधीन पहली बार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ है ; या

(ii) जिसमें खनिज तेल का परिष्करण प्रारंभ हुआ है ।

धारा 80इअ की उपधारा (9) में नया परंतुक अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस उपधारा के अधीन कोई कटौती खनिज तेल के परिष्करण में लगे हुए किसी उपक्रम को अनुज्ञात नहीं होगी, यदि वह परिष्करण का कार्य 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्रारंभ करता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (11ग) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि पांच वर्ष की कर छूट को बृहतर मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलौर और अहमदाबाद नगर क्षेत्रों और फरीदाबाद, गुडगांव, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और गांधीनगर और सिकंदराबाद नगर को छोड़कर भारत में कहीं भी अवस्थित अस्पतालों तक विस्तारित किया जा सके । किसी शहरी बस्ती वाला क्षेत्र वह क्षेत्र होगा जो 2001 की जनगणना के आधार पर उस शहरी बस्ती में सम्मिलित किया गया है । उक्त कर फायदा ऐसे अस्पताल को उपलब्ध होगा, जो 1 अप्रैल, 2008 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय संनिर्मित किया गया है और उसने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है या आरंभ करता है । आरंभिक निर्धारण को उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें अस्पताल का कारबार कार्य करना आरंभ करता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 16—आय-कर अधिनियम की धारा 80इअ का संशोधन करने के लिए है जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र में होटलों और कन्वेंशन केन्द्रों के कारबार से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती से संबंधित है ।

अधिनियम की धारा 80इअ ऐसे दो, तीन और चार सितारा प्रवर्ग के नए होटलों और कन्वेंशन केन्द्रों के लिए, जिनका निर्माण 1 अप्रैल, 2007 से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय हुआ है और उसने कार्य करना आरंभ किया है या करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए शतप्रतिशत कर कटौती का उपबंध करती है । उपरोक्त फायदे का उपभोग करने के लिए होटल या कन्वेंशन केन्द्र को उस विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अवस्थित होना चाहिए, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और फरीदाबाद, गुडगांव, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों के रूप में परिभाषित किए गए हैं ।

इस धारा में उपलब्ध कर फायदे की परिधि को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल वाले विनिर्दिष्ट जिले में अवस्थित ऐसे दो सितारा, तीन सितारा और चार सितारा प्रवर्ग के नए होटलों के लिए भी विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है, यदि ऐसे होटल का निर्माण 1 अप्रैल, 2008 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय हुआ है और उसने कार्य करना आरंभ किया है या करता है । आगरा, जलगांव, औरंगाबाद, कांचीपुरम, पुरी, भरतपुर, छतरपुर, तंजावुर, बेलारी, दक्षिण 24 परगना (2001 की जनगणना के आधार पर कोलकाता शहरी क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर) चमोली, रायसेन, गया, भोपाल, पंचमहल, कामरूप, गोलपाड़ा और नागांव, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा, दार्जिलिंग और नीलगिरी

जिलों को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल वाले विनिर्दिष्ट जिला बनाए जाने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 17—आय-कर अधिनियम की धारा 88ड का संशोधन करने के लिए है जो प्रतिभूति संव्यवहार कर की बाबत रिबेट से संबंधित है ।

संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष में या उसके पश्चात् आय-कर की कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा ।

खंड 18 और खंड 19— आय-कर अधिनियम की धारा 111क और 115कघ का संशोधन करने के लिए हैं जो कतिपय दशाओं में अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर से संबंधित हैं ।

धारा 111क और धारा 115कघ के विद्यमान उपबंधों के अधीन ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के अंतरण से जो किसी कंपनी में साधारण शेयरों-नुख निधि की यूनित है, अंतरण से उद्भूत अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर जहां ऐसा संव्यवहार प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभावी है वहां दस प्रतिशत की विशेष दर से कर का उपबंध किया गया है ।

ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ पर कर की दर को बढ़ाकर पन्द्रह प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 20—आय-कर अधिनियम की धारा 115जख का संशोधन करने के लिए है जो कतिपय कंपनियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा में यह उपबंध है कि यदि किसी पूर्ववर्ष की बाबत आय कर अधिनियम के अधीन संगणित कुल आय पर संदेय आय कर उसके बही लाभ के साढ़े सात प्रतिशत से कम है (निर्धारण वर्ष 2007-2008 से सुसंगत पूर्ववर्ष और आगे के लिए दस प्रतिशत) तो ऐसे बही लाभ को निर्धारित की कुल आय समझा जाएगा और सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए संदेय कर ऐसे बही लाभ का साढ़े सात प्रतिशत (निर्धारण वर्ष 2007-2008 से सुसंगत पूर्ववर्ष और आगे के लिए दस प्रतिशत) होगा । उपधारा (2) लाभ-हानि लेखा तैयार करने से संबंधित है । उपधारा (2) के पश्चात् स्पष्टीकरण के अनुसार, बही लाभ से कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग 2 और 3 के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए लाभ-हानि लेखा में दिखाया गया शुद्ध लाभ अभिप्रेत है, जिसमें उस धारा में यथाविनिर्दिष्ट कतिपय समायोजनों को जोड़ दिया गया है या उससे घटा दिया गया है । उपरोक्त स्पष्टीकरण का खंड (क), अन्य बातों के साथ यह उपबंध करता है कि बही लाभ को संदत्त या संदेय आय कर की रकम और उसके लिए व्यवस्था, यदि लाभ और हानि-लेखा से विकलित की जाती है, बढ़ा दिया जाएगा ।

धारा 115जख के स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित करने और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के खंड (छ) के पश्चात् एक नया खंड अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बही लाभ को संदत्त या संदेय आय-कर की रकम और उसके लिए व्यवस्था, यदि लाभ और हानि लेखा से विकलित की जाती है, से बढ़ा दिया जाएगा ।

इसके अतिरिक्त स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् एक नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए आय-कर की रकम में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,—

(i) क्रमशः धारा 115ण या धारा 115द के अधीन वितरित लाभ या वितरित आय पर कर ;

(ii) इस अधिनियम के अधीन प्रभारित कोई ब्याज ;

(iii) समय-समय पर केन्द्रीय अधिनियमों द्वारा यथा उद्गृहीत अधिभार, यदि कोई हो ;

(iv) समय-समय पर केन्द्रीय अधिनियमों द्वारा आय-कर पर उद्गृहीत शिक्षा-उपकर, यदि कोई हो ; और

(v) समय-समय पर केन्द्रीय अधिनियमों द्वारा आय-कर पर उद्गृहीत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा-उपकर, यदि कोई हो ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2001 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2001-2002 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 21—आय-कर अधिनियम की धारा 115ण का संशोधन करने के लिए है जो देशी कंपनियों के वितरित लाभ पर कर से संबंधित है। उक्त धारा की उपधारा (1) अन्य बातों के साथ यह उपबंध करती है कि ऐसी कंपनी द्वारा लाभांशों के रूप में घोषित, वितरित या संदत्त रकम, वितरित लाभों पर अतिरिक्त आय-कर या कर से पंद्रह प्रतिशत की दर पर प्रभाविता होगी।

एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम को वर्ष के दौरान देशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश की रकम, यदि कोई हो, से घटा दिया जाएगा, यदि—

(क) लाभांश की रकम उसकी समनुषंगी से प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि समनुषंगी कंपनी ने लाभांश की उस रकम पर इस धारा के अधीन कर का संदाय किया है ; और

(ग) देशी कंपनी किसी अन्य कंपनी की समनुषंगी नहीं है ।

नई उपधारा यह भी उपबंध करती है कि लाभांश की उसी रकम को एक से अधिक बार कम नहीं किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए, समनुषंगी कंपनी किसी दूसरी कंपनी की समनुषंगी होगी, यदि ऐसी अन्य कंपनी उस कंपनी की साधारण शेयर पूंजी के अभिहित मूल्य में आधे से अधिक शेयर धारण करती है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा ।

खंड 22—आय-कर अधिनियम की धारा 115बख का संशोधन करने के लिए है जो अनुषंगी फायदों से संबंधित है ।

उक्त धारा में “विनिर्दिष्ट प्रतिभूति” को परिभाषित किया गया है जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ कर्मचारी स्टाक विकल्प भी है । इस परिभाषा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि जहां कर्मचारी स्टाक विकल्प मंजूर किया गया है वहां इसके अंतर्गत ऐसी कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना या स्कीम के अधीन प्रस्थापित प्रतिभूतियों को सम्मिलित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि अनुषंगी फायदे नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए समझे जाएंगे यदि नियोजक ने अपने कारबार या वृत्ति (जिसके अंतर्गत कोई क्रियाकलाप भी है, चाहे ऐसा क्रियाकलाप आय, लाभ या अभिलाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता हो अथवा नहीं) के अनुक्रम में मनोरंजन, आतिथ्य, सम्मेलन, विक्रय संवर्धन (जिसके अंतर्गत प्रचार भी है), आदि जैसे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों पर कोई व्यय उपगत किया है या उनके लिए कोई संदाय किया है ।

उक्त उपधारा के खंड (ख) का उपखंड (i) और उपखंड (ii) कतिपय व्यय को अनुषंगी फायदा कर की संगणना के लिए आतिथ्य व्यय से अपवर्जित करते हैं । यह उपबंध करने के लिए खंड (ख) का और संशोधन करने का प्रस्ताव है कि ऐसे अहस्तांतरणीय पूर्व संदत्त ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मील कार्ड पर कोई व्यय या उसके द्वारा किया गया संदाय, जो केवल भोजन स्थलों या दुकानों पर ही उपयोग के योग्य है और ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करता है, जो विहित की जाएं, को भी अनुषंगी फायदा कर की संगणना के लिए आतिथ्य व्यय से अपवर्जित किया जा सके ।

इसके अतिरिक्त, उक्त उपधारा के खंड (ड) का स्पष्टीकरण कतिपय व्यय को अनुषंगी फायदा कर की संगणना के लिए कर्मचारी कल्याण व्यय से अपवर्जित करता है । इस स्पष्टीकरण में यह उपबंध करके अपवर्जन की परिधि को विस्तारित करने का प्रस्ताव है कि,—

(i) कर्मचारी के बालकों के लिए शिशु गृह सुविधा प्रदान करने ; या

(ii) ऐसे किसी खिलाड़ी को प्रायोजित करने, जो कर्मचारी है ; या

(iii) कर्मचारियों के लिए खेलकूद समारोह आयोजित करने,

पर उपगत व्यय या किए गए संदाय को भी अनुषंगी फायदा कर के संगणन के लिए कर्मचारी कल्याण के संबंध में व्यय नहीं समझा जाएगा ।

इसके अतिरिक्त, उक्त उपधारा का खंड (ट) प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वास सुविधा से भिन्न अतिथि गृह की प्रकृति की किसी वास सुविधा के अनुरक्षण संबंधी व्यय के लिए अनुषंगी फायदों के रूप में उपबंध करने के लिए है। इस खंड का लोप करने का प्रस्ताव है जिससे कि इस व्यय को अनुषंगी फायदा कर के अधीन न रखा जाए ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 23—आय-कर अधिनियम की धारा 115बग का संशोधन करने के लिए है जो अनुषंगी फायदों के मूल्य से संबंधित है ।

धारा 115बग, धारा 115बख में विनिर्दिष्ट विभिन्न अनुषंगी फायदों के मूल्यांकन का उपबंध करती है । धारा 115बग की उपधारा (1) के खंड (ग) में यह उपबंध है कि धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (ट) में निर्दिष्ट व्यय से संबंधित अनुषंगी फायदे का मूल्य उन व्ययों का बीस प्रतिशत होगा । इसी प्रकार उक्त उपधारा के खंड (घ) में यह उपबंध है कि धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (ठ) से खंड (त) में निर्दिष्ट अनुषंगी फायदों का मूल्य व्ययों का पचास प्रतिशत होगा । खंड 115बख की उपधारा (2) के खंड (ठ) में वर्णित उत्सव समारोह पर व्ययों के प्रयोजनों के लिए अनुषंगी फायदे का मूल्य तदनुसार पचास प्रतिशत पर लगाया जाता है ।

धारा 115बग की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ), दोनों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उत्सव समारोहों पर व्यय का केवल 20 प्रतिशत अनुषंगी फायदे का मूल्य समझा जाएगा और न कि 50 प्रतिशत जैसा कि विद्यमान उपबंध में है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-2010 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 24—आय-कर अधिनियम की धारा 115बघ का संशोधन करने के लिए है जो अनुषंगी फायदों की विवरणी से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण का खंड (क) उसके अधीन विनिर्दिष्ट निर्धारितियों के प्रवर्गों द्वारा अनुषंगी फायदों की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख का उपबंध करता है । अधिनियम के उक्त उपबंधों के अधीन, किसी कंपनी या ऐसे किसी व्यक्ति (कंपनी से भिन्न) की दशा में, जिसके लेखे इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, अनुषंगी फायदों की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख निर्धारण वर्ष की 31 अक्टूबर है ।

उक्त खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनुषंगी फायदों की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख निर्धारण वर्ष की 30 सितंबर होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा ।

खंड 25—आय-कर अधिनियम की धारा 115बड का संशोधन करने के लिए है जो निर्धारण से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 115बघ के अधीन विवरणी दी गई है वहां ऐसी विवरणी पर निम्नलिखित रीति से कार्यवाही की जाएगी, अर्थात् :—

(क) अनुषंगी फायदे के मूल्य की संगणना निम्नलिखित समायोजन करने के पश्चात् की जाएगी, अर्थात् :—

(i) विवरणी में कोई गणित संबंधी गलती ; या

(ii) कोई गलत दावा, यदि ऐसा गलत दावा विवरणी में किसी सूचना से प्रकट है ;

(ख) कर या ब्याज की संगणना, यदि कोई है, खंड (क) के अधीन संगणित अनुषंगी फायदे के मूल्य के आधार पर की जाएगी ;

(ग) निर्धारिती द्वारा संदेय राशि या उसे देय प्रतिदाय की रकम का अवधारण संदत्त किसी अग्रिम कर, स्वनिर्धारण के आधार पर संदत्त कर और कर या ब्याज के रूप में अन्यथा संदत्त किसी रकम का खंड (ख) के अधीन संगणित कर और ब्याज, यदि कोई हो, में समायोजन के पश्चात् किया जाएगा ;

(घ) कोई सूचना खंड (ग) के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय किए जाने के लिए अवधारित राशि या उसे देय प्रतिदाय की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए तैयार या उत्पन्न की जाएगी और निर्धारिती को भेजी जाएगी ; और

(ङ) खंड (ग) के अधीन अवधारण के अनुसरण में निर्धारिती को शोध्य प्रतिदाय की रकम निर्धारिती को मंजूर की जाएगी :

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि इस उपधारा के अधीन कोई सूचना उस वित्तीय वर्ष, जिसमें विवरणी दी गई है, अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं भेजी जाएगी ।

उक्त उपधारा में “विवरणी में किसी सूचना से प्रकट गलत दावा” पद को परिभाषित किया गया है । यह भी स्पष्ट किया गया है कि विवरणी की अभिस्वीकृति उस दशा में सूचना समझी जाएगी जहां खंड (ग) के अधीन निर्धारिती द्वारा कोई राशि संदेय नहीं है या उसे प्रतिदेय नहीं है जहां खंड (क) के अधीन कोई समायोजन नहीं किया गया है ।

उक्त धारा में नई उपधारा (1क), उपधारा (1ख) और उपधारा (1ग) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है । उपधारा (1क) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के अधीन विवरणियों के संबंध में कार्यवाही करने के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड उस उपधारा के अधीन अपेक्षित रूप में निर्धारिती द्वारा संदेय कर या उसे देय प्रतिदाय का शीघ्रता से अवधारण करने की दृष्टि से विवरणियों की कार्यवाहियों के केन्द्रीयकरण के लिए स्कीम बना सकेगा । उक्त उपधारा (1ख) यह प्रस्ताव करती है कि उपधारा (1क) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि विवरणियों की कार्यवाही से संबंधित इस अधिनियम के कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों या अनुकूलनों के साथ लागू होंगे जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं तथापि, 31 मार्च, 2009 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा। उपधारा (1ग) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1ख) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उपधारा (1क) के अधीन बनाई गई स्कीम के साथ, अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे ।

खंड 26—आय-कर अधिनियम में नई धारा 115बटख अंतःस्थापित करने के लिए है जो कर्मचारी द्वारा कर के समझे गए संदाय से संबंधित है ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य श्रेयों के आबंटन की बाबत किसी अनुषंगी फायदा कर का नियोजक द्वारा संदाय किया गया है और बाद में कर्मचारी से उसकी वसूली की गई है, वहां यह समझा जाएगा कि इस प्रकार वसूल किया गया अनुषंगी फायदा कर उस कर्मचारी द्वारा केवल उस सीमा तक उसे उपलब्ध कराए गए अनुषंगी फायदे के मूल्य के संबंध में संदत्त कर है, जिस तक उसकी रकम धारा 115बग की उपधारा (1) के खंड (खक) के अधीन यथा अवधारित, ऐसे कर्मचारी को प्रदान किए गए अनुषंगी फायदे के मूल्य से संबंधित है ।

नई धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी जहां कर्मचारी से वसूल किए गए अनुषंगी फायदा कर को उपधारा (1) के अधीन ऐसे कर्मचारी द्वारा संदत्त कर समझा गया है, वहां ऐसा कर्मचारी, कर के ऐसे संदाय में से इस अधिनियम के अधीन किसी प्रतिदाय के लिए; या कर के ऐसे संदाय का अन्य आय संबंधी कर दायित्व के संबंध में या किसी अन्य कर दायित्व के संबंध में किसी मुजरे का दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 27—आय-कर अधिनियम की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है जो आय की विवरणी से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 का खंड (क) उसके अधीन विनिर्दिष्ट निर्धारितियों के प्रवर्गों द्वारा आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख का उपबंध करता है । अधिनियम के उक्त उपबंधों के अधीन, किसी कंपनी या ऐसे किसी व्यक्ति (कंपनी से भिन्न) की दशा में, जिसके लेखाओं की, इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षा कराई जानी अपेक्षित है या किसी फर्म में कार्यरत भागीदार की दशा में, जिसके लेखाओं की इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षा कराई जानी अपेक्षित है, आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख निर्धारण वर्ष के अक्टूबर का 31वां दिन है ।

उक्त खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय की ऐसी विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख निर्धारण वर्ष की 30 सितंबर होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण में उन शर्तों का उपबंध है जिनका पूरा किया जाना अपेक्षित है जिससे आय की किसी विवरणी को त्रुटिपूर्ण न माना जाए ।

उक्त स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में यह उपबंध है कि यदि विवरणी के साथ उस कर का सबूत जिसके 1 अप्रैल, 2008 के पूर्व स्रोत पर काटे जाने या संगृहीत किए जाने का दावा किया गया है, नहीं लगाया गया है तो वह विवरणी त्रुटिपूर्ण विवरणी समझी जाएगी ।

उक्त तारीख के प्रतिनिर्देश का लोप करने का प्रस्ताव है जिससे उस कर के सबूत से संबंधित जिसके स्रोत पर काटे जाने या संगृहीत किए जाने का दावा किया गया है, उक्त उपखंड में निर्दिष्ट अग्रिम कर के संदाय के सबूत से संबंधित उपबंधों के समान उपबंध किए जा सकें ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा ।

खंड 28—आय-कर अधिनियम की धारा 142 का संशोधन करने के लिए है जो निर्धारण से पूर्व जांच के संबंध में है ।

उक्त धारा 142 की उपधारा (2क) से उपधारा (2घ), जहां लेखाओं की प्रकृति और जटिलता ऐसी संपरीक्षा की अपेक्षा करे, वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट की सहायता प्राप्त करने के लिए विशेष संपरीक्षा का आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी की शक्ति के बारे में है ।

उक्त धारा की उपधारा (2ग) उस अवधि को विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर संपरीक्षा रिपोर्ट दी जानी है । उक्त उपधारा के परंतुक में यह उपबंध है कि निर्धारण अधिकारी स्वप्रेरणा से या इस निमित्त निर्धारिती द्वारा आवेदन किए जाने पर तथा किसी अच्छे और पर्याप्त कारण से संपरीक्षा रिपोर्ट देने की उक्त कालावधि को बढ़ा सकेगा ।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी स्वप्रेरणा से इस निमित्त निर्धारिती द्वारा आवेदन किए जाने पर तथा किसी अच्छे और पर्याप्त कारण से उक्त कालावधि को उतनी अतिरिक्त कालावधि या कालावधियों तक बढ़ा सकेगा जितनी वह ठीक समझता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा ।

खंड 29—आय-कर अधिनियम की धारा 143 का संशोधन करने के लिए है जो निर्धारण से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना के उत्तर में विवरणी दी गई है वहां ऐसी विवरणी पर निम्नलिखित रीति से कार्यवाही की जाएगी, अर्थात् :—

(क) कुल आय या हानि की संगणना निम्नलिखित समायोजन करने के पश्चात् की जाएगी, अर्थात् :—

(i) विवरणी में कोई गणित संबंधी गलती ; या

(ii) कोई गलत दावा, यदि ऐसा गलत दावा विवरणी में किसी सूचना से प्रकट है ;

(ख) कर या ब्याज की संगणना, यदि कोई है, खंड (क) के अधीन संगणित कुल आय के आधार पर की जाएगी ;

(ग) निर्धारिती द्वारा संदेय राशि या उसे देय प्रतिदाय की रकम, स्रोत पर काटे गए किसी कर, स्रोत पर संगृहीत किसी कर, संदत्त किसी अग्रिम कर, धारा 90 या धारा 90क के अधीन किसी करार के अधीन अनुज्ञेय किसी राहत या धारा 91 के अधीन अनुज्ञेय राहत अध्याय 8 के भाग क के अधीन अनुज्ञेय किसी रिबेट, स्वनिर्धारण पर संदत्त किसी कर और कर या ब्याज के रूप में अन्यथा संदत्त किसी रकम का खंड (ख) के अधीन संगणित कर और ब्याज, यदि कोई हो, में समायोजन के पश्चात् अवधारित की जाएगी ;

(घ) खंड (ग) के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय किए जाने के लिए अवधारित राशि या उसे देय प्रतिदाय की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना तैयार और उत्पन्न की जाएगी और निर्धारिती को भेजी जाएगी ; और

(ङ) खंड (ग) के अधीन अवधारण के अनुसरण में निर्धारिती को शोध्य प्रतिदाय की रकम निर्धारिती को दी जाएगी :

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि सूचना निर्धारिती को ऐसे मामले में भेजी जाएगी जहां निर्धारिती द्वारा विवरणी में घोषित हानि कम कर दी गई है किंतु उसके द्वारा कोई कर या ब्याज संदेय नहीं है या उसे प्रतिदाय देय नहीं है :

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि इस उपधारा के अधीन कोई सूचना उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं भेजी जाएगी जिसमें विवरणी दी गई थी ।

आगे उक्त उपधारा में “विवरणी में किसी सूचना से प्रकट गलत दावा” पद को परिभाषित किया गया है । यह भी स्पष्ट किया गया है कि विवरणी की अभिरक्षीकृति उस दशा में सूचना समझी जाएगी जहां खंड (ग) के अधीन निर्धारिती द्वारा कोई राशि संदेय नहीं है या उसे प्रतिदेय नहीं है और जहां खंड (क) के अधीन कोई समायोजन नहीं किया गया है ।

उक्त धारा में नई उपधारा (1क), उपधारा (1ख) और उपधारा (1ग) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है । उपधारा (1क) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के अधीन विवरणी पर कार्यवाही करने के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड उस उपधारा के अधीन अपेक्षित रूप में निर्धारिती द्वारा संदेय कर या उसे देय प्रतिदाय का शीघ्रता से अवधारण करने की दृष्टि से विवरणियों की कार्यवाहियों के केन्द्रीयकरण के लिए स्कीम बना सकेगा । उपधारा (1ख) यह प्रस्ताव करती है कि उपधारा (1क) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि विवरणियों की कार्यवाही से संबंधित इस अधिनियम के कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों या अनुकूलनों के साथ लागू होंगे जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं । तथापि 31 मार्च, 2009 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा। उपधारा (1ग) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1ख) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उपधारा (1क) के अधीन बनाई गई स्कीम के साथ, अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

उक्त धारा का और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है जिससे कि उसकी उपधारा (2) के खंड (ii) के परंतुक को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित किया जा सके कि खंड (ii) के अधीन कोई सूचना उस वित्तीय वर्ष के अंत से छह मास की समाप्ति के पश्चात्, जिसमें विवरणी दी गई है, निर्धारिती पर तामील नहीं की जाएगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे ।

खंड 30—आय-कर अधिनियम की धारा 147 का संशोधन करने के लिए है जो निर्धारण से छूट गई आय से संबंधित है ।

यह उपबंध करने के लिए एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि निर्धारण अधिकारी ऐसी आय से भिन्न किसी आय का, जो किसी अपील, निर्देश या पुनरीक्षण की विषय-वस्तु है, निर्धारण या पुनःनिर्धारण कर सकेगा, जो कर से प्रभावी है और निर्धारण से छूट गई है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा ।

खंड 31—आय-कर अधिनियम की धारा 151 का संशोधन करने के लिए है जिसमें ऐसे मामले अंतर्वलित है जो सूचना जारी किए जाने के लिए मंजूरी के संबंध में है ।

धारा 151 के विद्यमान उपबंधों के अधीन, कतिपय परिस्थितियों में, धारा 148 के अधीन सूचना जारी किए जाने के लिए मामले की उपयुक्तता के बारे में निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए कारणों के आधार पर, यथास्थिति, संयुक्त आयुक्त, आयुक्त या मुख्य आयुक्त का समाधान अपेक्षित है ।

धारा 151 की उपधारा (2) के पश्चात् स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह घोषित किया जा सके कि, यथास्थिति, संयुक्त आयुक्त, आयुक्त या मुख्य आयुक्त के लिए, धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए मामले की उपयुक्तता के बारे में निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए कारणों के आधार पर समाधान हो जाने के पश्चात् स्वयं सूचना जारी करना आवश्यक नहीं है ।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 1998 से, भूतलक्षी रूप से, प्रभावी होगा ।

खंड 32 से खंड 36—आय-कर अधिनियम की धारा 153, धारा 153क और धारा 153ख, धारा 153ग और धारा 153घ का संशोधन करने के लिए हैं जो निर्धारणों और पुनःनिर्धारणों को पूरा करने के लिए समय-सीमा, तलाशी या अध्यक्षता की दशा में निर्धारण को पूरा करने के लिए समय-सीमा, आदि से संबंधित है ।

प्रस्तावित संशोधन धारा 153 में नया परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां समझौता आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही का धारा 245जक के अधीन उपशमन हो जाता है वहां, यथास्थिति, निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनः संगणना का आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध उक्त धारा में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि, धारा 245जक की उपधारा (4) के अधीन अवधि के समायोजन के पश्चात्, एक वर्ष से कम की नहीं होगी ; और जहां परिसीमा की ऐसी अवधि एक वर्ष से कम की है वहां उसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया समझा जाएगा ।

इसके अतिरिक्त धारा 149, धारा 153ख, धारा 154, धारा 155, धारा 158खड और धारा 231 के अधीन परिसीमा की अवधि का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए और, यथास्थिति, धारा 243 या धारा 244 या धारा 244क के अधीन ब्याज के संदाय के प्रयोजनों के लिए, यह उपबंध भी तदनुसार लागू होगा।

धारा 153 का यह संशोधन 1 जून, 2007 से भूतलक्षी रूप से लागू होगा।

यह उपबंध करने के लिए धारा 153 में नई उपधारा (4) अंतःस्थापित किए जाने का और प्रस्ताव है कि इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में और धारा 153क की उपधारा (2) और धारा 153ख की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में निर्धारण या पुनःनिर्धारण का आदेश, जो धारा 153क की उपधारा (2) के अधीन पुनःप्रवर्तित हो गया है, ऐसे पुनःप्रवर्तन के मास के अंत से एक वर्ष के भीतर या इस धारा में अथवा धारा 153ख की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्ती हो, किया जाएगा ।

धारा 153क के विद्यमान उपबंध को उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किए जाने का प्रस्ताव है और यह उपबंध करने के लिए एक नई उपधारा (2) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है कि यदि उपधारा (1) के अधीन आरंभ की गई किसी कार्यवाही या किए गए निर्धारण या पुनःनिर्धारण के किसी आदेश को अपील में या किसी अन्य विधिक कार्यवाही में बातिल कर दिया गया है, तो इस धारा की उपधारा (1) या धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में निर्धारण या पुनःनिर्धारण, जिसका उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन उपशमन हो गया है, आयुक्त द्वारा ऐसे बातिलीकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से, पुनःप्रवर्तित हो जाएगा । इस धारा का परंतुक यह उपबंध करने का प्रस्ताव करता है कि यदि बातिलीकरण का ऐसा आदेश अपास्त कर दिया जाता है तो ऐसा पुनःप्रवर्तन प्रभावी नहीं रहेगा । इसके अतिरिक्त, धारा 153क के उपबंधों को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किए जाने को ध्यान में रखते हुए उपधारा (1) के दूसरे परंतुक का “इस धारा में निर्दिष्ट” शब्दों के स्थान पर, “इस उपधारा में निर्दिष्ट” शब्दों को रखते हुए संशोधन किया गया है ।

धारा 153क का खंड (ख) उस पूर्ववर्ष से जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली जाती है या धारा 132क के अधीन अध्यक्षता की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक

पूर्व के छह निर्धारण वर्षों की कुल आय के निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने का उपबंध करता है।

धारा 153ख की उपधारा (1) का खंड (क) धारा 153क के खंड (ख) में निर्दिष्ट छह निर्धारण वर्षों की अवधि के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष की बाबत कुल आय के निर्धारण या पुनःनिर्धारण को पूरा करने के लिए समय-सीमा का उपबंध करता है। इस उपधारा का खंड (ख) उस पूर्ववर्ष से, जिसमें ऐसी तलाशी ली जाती है या अध्ययन की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष की बाबत निर्धारण पूरा करने के लिए समय-सीमा का उपबंध करता है।

यह उपबंध करने के लिए धारा 153ख की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में एक नया खंड (vii) अंतःस्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है कि धारा 153क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनःनिर्धारण की किसी कार्यवाही या आदेश के बातिलीकरण की तारीख से प्रारंभ होने वाली और ऐसी तारीख तक की अवधि जिसको आयुक्त द्वारा ऐसे बातिलीकरण के आदेश को अपास्त करने वाला आदेश प्राप्त होता है, धारा 153ख के प्रयोजनों के लिए परिसीमा की अवधि की गणना करने से अपवर्जित कर दी जाएगी। उपधारा (1) के खंड (क) में और स्पष्टीकरण के परंतुक में, “धारा 153क” शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “धारा 153क की उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखने के लिए पारिणामिक संशोधन किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त धारा 153ग और धारा 153घ में “धारा 153क” शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “धारा 153क की उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखने के लिए पारिणामिक संशोधन किए गए हैं।

ये संशोधन 1 जून, 2003 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे।

खंड 37—आय-कर अधिनियम की धारा 156 का संशोधन करने के लिए है जो मांग की सूचना से संबंधित है।

धारा 156 के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि जहां इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप कोई कर, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य राशि संदेय है वहां निर्धारण अधिकारी इस प्रकार संदेय राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्रारूप में मांग की सूचना निर्धारिती पर तामील करेगा।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा संदाय किए जाने के लिए किसी राशि का अवधारण किया जाता है वहां उस उपधारा के अधीन सूचना इस धारा के प्रयोजनों के लिए मांग की सूचना समझी जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

खंड 38—आय-कर अधिनियम की धारा 191 का संशोधन करने के लिए है जो प्रत्यक्ष संदाय के संबंध में है।

उक्त धारा का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि यदि धारा 200 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति और धारा 194 में निर्दिष्ट प्रधान अधिकारी और कंपनी संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करती है और ऐसे कर को निर्धारिती द्वारा सीधे संदत्त नहीं किया गया है तो ऐसा व्यक्ति, प्रधान अधिकारी और कंपनी को, ऐसे किन्हीं अन्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो वह उपगत करे, ऐसे कर की बाबत धारा 201 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा।

इस प्रकार उक्त स्पष्टीकरण धारा 200 में निर्दिष्ट व्यक्तियों को अपनी परिधि में लाता है। धारा 200 अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करने वाले ऐसे व्यक्ति का उल्लेख करती है और जिससे इस प्रकार काटी गई राशि को विहित समय के भीतर केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करने की अपेक्षा की जाती है। अतः इस परंतुक में इस निर्वचन के लिए गुंजाइश है कि ऐसे व्यक्ति को जिससे स्रोत पर कर की कटौती करने की अपेक्षा है किन्तु वह ऐसी कटौती नहीं करता है, धारा 201 के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाएगा। ऐसा कोई निर्वचन विधान के आशय के विपरीत है।

अतः प्रस्तावित संशोधन उक्त स्पष्टीकरण को यह स्पष्ट करने के लिए प्रतिस्थापित करने के लिए है कि कोई व्यक्ति जिससे स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित है किन्तु ऐसा करने में असफल रहता है, धारा 201 के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती भी समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 जून, 2003 से, भूतलक्षी रूप से, प्रभावी होगा।

खंड 39—आय-कर अधिनियम की धारा 193 का संशोधन करने के लिए है जो प्रतिभूतियों पर ब्याज से संबंधित है।

धारा 193 किसी निवासी को संदेय प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में किसी आय पर कर की कटौती के लिए उपबंध करती है।

उक्त धारा का प्रस्तावित संशोधन किसी कंपनी द्वारा जारी किसी प्रतिभूति पर, जहां ऐसी प्रतिभूति डिमैटिरियलाइज रूप में है और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, संदेय किसी ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती से छूट देने के लिए है।

यह संशोधन 1 जून, 2008 से प्रभावी होगा।

खंड 40—आय-कर अधिनियम की धारा 194ग का संशोधन करने के लिए है जो ठेकेदारों और उप ठेकेदारों को संदाय के संबंध में है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में वे अस्तित्व विनिर्दिष्ट हैं जो निवासी ठेकेदार को संदायों पर स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन अस्तित्वों में कुछ व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय सम्मिलित हैं किन्तु इनमें सभी आम व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय सम्मिलित नहीं हैं।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक व्यक्ति-संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, उक्त उपधारा के अधीन कर पर आय-कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी है।

यह संशोधन 1 जून, 2008 से प्रभावी होगा।

खंड 41—आय-कर अधिनियम की धारा 195 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य राशियों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि कोई व्यक्ति, जो किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को, किसी ब्याज का या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य किसी अन्य राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय जमा करते समय या उसका नकद रूप में या बैंक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त दरों के अनुसार उस पर आय-कर की कटौती करेगा।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा में उपधारा (6) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी राशि के संदाय से संबंधित जानकारी ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में देगा, जो बोर्ड द्वारा विहित की जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

खंड 42—आय-कर अधिनियम की धारा 199 का संशोधन करने के लिए है जो कटौती किए गए कर की बाबत मुजरा से संबंधित है।

प्रस्तावित उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसी कोई कटौती जो इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार की गई है और केन्द्रीय सरकार को संदत्त की गई है, यथास्थिति, उस व्यक्ति की ओर से जिसकी आय से कटौती की गई थी या प्रतिभूति के स्वामी की या निक्षेपकर्ता या संपत्ति के स्वामी की या यूनितधारक की अथवा शेयर धारक की ओर से कर का संदाय समझी जाएगी।

प्रस्तावित उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसी कोई राशि, जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है और जिसका केन्द्रीय सरकार को संदाय कर दिया गया है, ऐसे व्यक्ति की ओर से जिसकी आय की बाबत कर का ऐसा संदाय किया गया है, संदत्त कर समझी जाएगी।

प्रस्तावित उपधारा (3) यह उपबंध करने के लिए है कि बोर्ड, इस अध्याय के उपबंधों के निबंधनानुसार कटौती किए गए कर या संदत्त कर की बाबत मुजरा देने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे नियम बना सकेगा जो वह आवश्यक समझे, जिनके अंतर्गत उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को और उस निर्धारण वर्ष को जिसके लिए ऐसा मुजरा किया जा सकेगा, मुजरा देने के प्रयोजनों के लिए नियम भी हैं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

खंड 43—आय-कर अधिनियम की धारा 201 का संशोधन करने के लिए है जो कटौती करने की या संदाय करने की असफलता के परिणामों के संबंध में है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो धारा 200 में निर्दिष्ट है और धारा 194 में निर्दिष्ट दशाओं में प्रधान अधिकारी और कंपनी जिसका वह प्रधान अधिकारी है, संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करता है या कटौती करने के पश्चात् उसे आय-कर अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित रूप में कर संदत्त करने में असफल रहता है तो ऐसे किन्हीं अन्य परिणामों पर, जो वह उपगत करे, कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे उस कर की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा।

इस प्रकार उक्त उपधारा, धारा 200 में निर्दिष्ट व्यक्तियों को अपनी परिधि में लाती है। धारा 200 अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करने वाले ऐसे व्यक्ति का उल्लेख करती है और जिससे इस प्रकार काटी गई राशि को विहित समय के भीतर केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करने की अपेक्षा की जाती है। अतः यह उपबंध इस निर्वचन के लिए गुंजाइश छोड़ता है कि ऐसे व्यक्ति को जिससे स्रोत पर कर की कटौती करने की अपेक्षा है किन्तु वह ऐसी कटौती नहीं करता है, धारा 201 के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाएगा। ऐसा निर्वचन विधान आशय के विपरीत है।

अतः प्रस्तावित संशोधन यह स्पष्ट करने के लिए उक्त उपधारा को प्रतिस्थापित करने के लिए है कि जहां कोई व्यक्ति स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित है किंतु ऐसा करने में असफल रहता है वहां वह धारा 201 के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती भी समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से, भूतलक्षी रूप से, प्रभावी होगा।

खंड 44—आय-कर अधिनियम की धारा 203 का संशोधन करने के लिए है जो कटौती किए गए कर के लिए प्रमाणपत्र से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि 1 अप्रैल, 2008 को या उसके पश्चात् निम्नलिखित को देने की अपेक्षा नहीं होगी—

- (i) स्रोत पर कटौती किए गए कर का प्रमाणपत्र ; या
- (ii) कर्मचारी को किसी गैर धनीय परिलब्धि के संबंध में नियोजक द्वारा केन्द्रीय सरकार को कर के रूप में संदत्त किसी राशि का प्रमाणपत्र।

प्रस्तावित संशोधन उक्त तारीख के स्थान पर 1 अप्रैल, 2010 को प्रतिस्थापित करता है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 31 मार्च, 2010 तक—

- (i) कर की कटौती करने वाला व्यक्ति स्रोत पर कटौती किए गए कर का प्रमाणपत्र उस व्यक्ति को देता रहेगा, जिसकी ओर से कटौतियों की गई थीं ; और
- (ii) कोई नियोजक कर्मचारी को किसी गैर धनीय परिलब्धि के संबंध में संदत्त कर का प्रमाणपत्र देता रहेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

खंड 45—आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है जो एलकोहाली लिकर, वनोत्पाद स्क्रैप आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (4) में यह उपबंध है कि उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार संगृहीत और केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त कोई रकम उस व्यक्ति की ओर से कर का संदाय समझी जाएगी, जिससे रकम संगृहीत की गई है और इस प्रकार संगृहीत रकम के लिए उसको मुजरा दिया जाएगा। उक्त धारा उस व्यक्ति को जिससे रकम संगृहीत की गई है, मुजरा देने के लिए स्रोत पर कटौती किए गए कर का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा भी करती है। उक्त उपधारा (4) का परंतुक यह उपबंध करता है कि 1 अप्रैल, 2008 के पश्चात् मुजरा, उक्त धारा की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट वार्षिक विवरण के आधार पर दिया जाएगा और स्रोत पर संगृहीत कर के लिए मुजरे का दावा करने हेतु आय की विवरणी के साथ कर के संग्रहण का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

स्रोत पर संगृहीत कर के लिए निर्धारिती को मुजरा अनुज्ञात करने की पद्धति को चल रही प्रौद्योगिकी और कारबार प्रक्रिया संबंधी परिवर्तनों पर विचार करते हुए कुछ

मात्रा में नमनीय बनाने की आवश्यकता है। इसलिए प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए उक्त उपधारा (4) को प्रस्थापित करने के लिए है कि इस धारा के उपबंधों के अनुसार संगृहीत केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त कोई रकम उस व्यक्ति की ओर से जिससे रकम संगृहीत की गई है, कर का संदाय समझी जाएगी और समय-समय पर बोर्ड द्वारा विहित किए गए नियमों के अनुसार किसी विशिष्ट निर्धारण वर्ष में इस प्रकार संगृहीत रकम के लिए उस व्यक्ति को मुजरा दिया जाएगा।

उक्त धारा की उपधारा (5) के पहले परंतुक के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि 1 अप्रैल, 2008 को या उसके पश्चात् स्रोत पर कर के संग्रहण का प्रमाणपत्र देने की अपेक्षा नहीं होगी।

प्रस्तावित संशोधन उक्त तारीख को 1 अप्रैल, 2010 से प्रतिस्थापित करता है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि वह व्यक्ति, जो कर संग्रहण करता है 31 मार्च, 2010 तक उस व्यक्ति को, जिससे रकम संगृहीत की गई है, स्रोत पर कटौती किए गए कर का प्रमाणपत्र देता रहेगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे।

खंड 46—आय-कर अधिनियम की धारा 254 का संशोधन करने के लिए है जो अपील अधिकरण के आदेशों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2क) यह उपबंध करती है कि आय-कर अपील अधिकरण, जहां संभव हो, प्रत्येक अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा 253 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपील फाइल की जाती है, अंत से चार वर्ष की अवधि के भीतर कर सकेगा।

इस उपधारा के पहले परंतुक में यह उपबंध है कि उक्त अपील अधिकरण किसी अपील से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में गुणागुण के आधार पर रोक आदेश पारित कर सकेगा। तथापि, रोक की ऐसी अवधि ऐसे आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन से अधिक की नहीं हो सकती और उक्त अपील अधिकरण अपील का निपटारा रोक की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करेगा।

इस उपधारा के दूसरे परंतुक में यह उपबंध है कि जहां अपील का निपटारा उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया गया है और अपील के निपटारे में विलंब निर्धारिती की ओर से नहीं है वहां अपील अधिकरण आरंभ में अनुज्ञात रोक की अवधि को आगे और बढ़ा सकेगा। तथापि, आरंभ में अनुज्ञात अवधि और इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि कुल मिलाकर 365 दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए। अपील अधिकरण से अपील का निपटारा विस्तारित अवधि के भीतर करने की अपेक्षा की जाती है।

इस उपधारा के तीसरे परंतुक में यह उपबंध है कि यदि ऐसी अपील का विनिश्चय आरंभ में अनुज्ञात की गई अवधि या इस प्रकार बढ़ाई गई या अनुज्ञात की गई अवधि या अवधियों के भीतर नहीं किया जाता है तो रोक आदेश ऐसी अवधि या अवधियों की समाप्ति के पश्चात् बातिल हो जाएगा।

इन उपबंधों के पीछे का आशय बहुत ही स्पष्ट रहा है कि अपील अधिकरण न तो आरंभिक आदेश में और न किसी पश्चात्पूर्वी आदेश में कुल मिलाकर 365 दिन की अवधि से अधिक रोक मंजूर नहीं कर सकता।

इस आशय को स्पष्ट करने के लिए यह प्रस्ताव है कि आय-कर अधिनियम की धारा 254 का संशोधन किया जाए और यह और उपबंध किया जाए कि आरंभ में अनुज्ञात अवधि और इस प्रकार बढ़ाई गई या अनुज्ञात की गई अवधि या अवधियां कुल मिलाकर किसी भी दशा में 365 दिन से अधिक नहीं होंगी, भले ही अपील के निपटारे में विलंब निर्धारिती की ओर से नहीं हुआ है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2008 से प्रभावी होगा।

खंड 47—आय-कर अधिनियम में नई धारा 268क अंतःस्थापित करने के लिए है जो आय-कर प्राधिकारियों द्वारा अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल किए जाने से संबंधित है।

प्रस्तावित धारा यह उपबंध करने के लिए है कि बोर्ड, समय-समय पर, अध्याय 20 के उपबंधों के अधीन किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा अपील या निर्देश के लिए आवेदन के फाइल किए जाने को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए, ऐसी धनीय सीमाएं नियत करते हुए, जो वह ठीक समझे, अन्य आय-कर प्राधिकारियों को आदेश या अनुदेश जारी कर सकेगा।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निर्देशों के अनुसरण में, किसी आय-कर प्राधिकारी ने किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में किसी निर्धारिती के मामले में किसी विवाद्यक के संबंध में, कोई अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल नहीं किया है तो इससे ऐसा प्राधिकारी, (क) किसी अन्य निर्धारण वर्ष में उसी निर्धारिती के ; या (ख) उसी या अन्य निर्धारण वर्ष में किसी अन्य निर्धारिती के मामले में उसी विवाद्यक पर कोई अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल करने से निवारित नहीं होगा ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि इस बात के होते हुए भी कि उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निर्देशों के अनुसरण में किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा कोई अपील या निर्देश के लिए कोई आवेदन फाइल नहीं किया गया है। किसी निर्धारिती के लिए, जो किसी अपील या निर्देश में पक्षकार है, यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह इस बात का प्रतिवाद करे कि आय-कर प्राधिकारी ने किसी मामले में कोई अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल न करने के बारे में विवादग्रस्त विवाद्यक पर विनिश्चय में उपमति दी है ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि इस अध्याय के अधीन फाइल की गई किसी अपील या निर्देश की सुनवाई करने वाला प्रत्येक अपील अधिकरण या न्यायालय इस धारा के अंतःस्थापन से पूर्व या पश्चात् समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेशों, अनुदेशों या विनिश्चयों और उन परिस्थितियों का ध्यान रखेगा, जिनके अधीन किसी मामले की बाबत ऐसी अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल किया गया था या नहीं ; और अधिकरण या न्यायालय तदनुसार विचाराधीन विवाद्यक के गुणागुण के आधार पर अपील या निर्देश का विनिश्चय करेगा ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसे प्रत्येक आदेश या अनुदेश या निर्देश को, जो बोर्ड द्वारा किसी अपील या निर्देश के लिए आवेदन को फाइल करने के संबंध में धनीय सीमाओं को नियत करने के लिए जारी किया गया है, उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 1999 से, भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

खंड 48—आय-कर अधिनियम की धारा 271 का संशोधन करने के लिए है जो विवरणियां न देने, सूचनाओं का अनुपालन न करने, आय को छिपाने आदि से संबंधित है ।

अध्याय 21 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन निर्धारण अधिकारी से शास्ति संबंधी कार्यवाहियों के दौरान समाधान करना अपेक्षित है । विधायी आशय यह था कि ऐसे समाधान को शास्ति के उद्ग्रहण के समय ही अभिलिखित किए जाने की अपेक्षा थी, न कि शास्ति आरंभ करने के समय । तथापि, इस मुद्दे के संबंध में कुछ न्यायिक निर्वाचन इस मत का पक्ष ले रहे हैं कि समाधान शास्ति संबंधी कार्यवाहियों के आरंभ किए जाने के समय भी अभिलिखित किया जाना चाहिए ।

अतः, आय-कर अधिनियम की धारा 271 में एक नई उपधारा (1ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारण या पुनः निर्धारण के किसी आदेश में किसी निर्धारिती की कुल आय या हानि की संगणना करने में कोई रकम जोड़ी या अननुज्ञात की जाती है और यदि ऐसे आदेश में उपधारा (1) के अधीन शास्ति संबंधी कार्यवाहियां आरंभ किए जाने का निर्देश अंतर्विष्ट है, तो निर्धारण या पुनः निर्धारण के ऐसे आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उपधारा (1) के अधीन शास्ति संबंधी कार्यवाहियां आरंभ किए जाने के लिए निर्धारण अधिकारी के समाधान का गठन करता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 1989 से, भूतलक्षी रूप से, प्रभावी होगा ।

खंड 49—आय-कर अधिनियम में नई धारा 273कक अंतःस्थापित करने के लिए है जो शास्ति से उन्मुक्ति देने की आयुक्त की शक्ति से संबंधित है ।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि कोई व्यक्ति शास्ति से उन्मुक्ति देने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, यदि, (क) उसने धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है और समझौते की कार्यवाहियों का उपशमन हो गया है ; और (ख) इस अधिनियम के अधीन शास्ति संबंधी की कार्यवाहियां आरंभ कर दी गई हैं ।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि शास्ति से उन्मुक्ति देने के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन उपशमन के पश्चात् शास्ति के अधिरोपण के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि आयुक्त ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् आय-कर प्राधिकारी को उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और अपनी आय और उस रीति का, जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न की गई है, पूर्ण और सही प्रकटन किया है ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति वापस ले ली जाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, जिसके लिए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी और तत्पश्चात् इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई हो ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी व्यक्ति को प्रदान की गई उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा किसी समय वापस ली जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान आय-कर प्राधिकारी से निर्धारण के लिए सारवान् किन्हीं विशिष्टियों को छिपाया था और मिथ्या साक्ष्य दिया था तथा तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसी किसी शास्ति के अधिरोपण के लिए दायी हो जाएगा, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति तब दायी होता यदि ऐसी उन्मुक्ति प्रदान न की गई होती ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा ।

खंड 50—आय-कर अधिनियम में नई धारा 278कख अंतःस्थापित करने के लिए है जो अभियोजन से उन्मुक्ति देने की आयुक्त की शक्ति से संबंधित है ।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि कोई व्यक्ति अभियोजन से उन्मुक्ति देने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, यदि उसने धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है और समझौते की कार्यवाहियों का उपशमन हो गया है ।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि अभियोजन से उन्मुक्ति देने के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन उपशमन के पश्चात् अभियोजन कार्यवाहियों के संस्थापन के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि आयुक्त ऐसे व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् आय-कर प्राधिकारी को उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और अपनी आय और उस रीति का, जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न की गई है, पूर्ण और सही प्रकटन किया है ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन 1 जून, 2007 के पूर्व किया गया है वहां आयुक्त इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा किसी समय वापस ले ली जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, जिसके अधीन रहते हुए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी और तत्पश्चात् इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई हो ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान की गई उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा किसी समय वापस ली जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान आय-कर प्राधिकारी से निर्धारण के लिए सारवान् किन्हीं विशिष्टियों को छिपाया था या मिथ्या साक्ष्य दिया था और तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए, जिसके संबंध में उन्मुक्ति प्रदान की गई थी या ऐसे किसी अन्य अपराध के संबंध में विचारण किया जा सकेगा, जिसके बारे में वह कार्यवाही के संबंध में दोषी रहा प्रतीत होता हो ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा ।

खंड 51—आय-कर अधिनियम में नई धारा 282क अंतःस्थापित करने के लिए है जो सूचनाओं और अन्य दस्तावेजों के अधिप्रमाणन से संबंधित है।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करने के लिए है कि जहां इस अधिनियम में यह अपेक्षित है कि किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा सूचना या अन्य दस्तावेज जारी किए जाने चाहिए, वहां ऐसी सूचना या अन्य दस्तावेज पर उस प्राधिकारी द्वारा हस्तलेख में हस्ताक्षर किए जाएंगे।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जारी की जाने, तामील की जाने या दी जाने वाली प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज, यदि अभिहित आय-कर प्राधिकारी का नाम और पद उस दस्तावेज पर मुद्रित, स्टांपित अथवा अन्यथा लिखित है, तो अधिप्रमाणित किया गया समझा जाएगा।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिहित आय-कर प्राधिकारी से उक्त धारा की उपधारा (2) में उपबंधित रीति से अधिप्रमाणन के पश्चात् ऐसी सूचना या अन्य दस्तावेज जारी करने, तामील करने या देने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई आय-कर प्राधिकारी अभिप्रेत है।

यह संशोधन 1 जून, 2008 से प्रभावी होगा।

खंड 52—एक नई धारा 292खख अंतःस्थापित करने के लिए है जो कतिपय परिस्थितियां अधिकथित करती हैं जिनमें सूचना विधिमाम्य समझी जाएंगी।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां कोई निर्धारिती किसी निर्धारण या पुनः निर्धारण से संबंधित किसी कार्यवाही में या जांच में उपसंजात हो गया है या सहयोग कर रहा है वहां यह समझा जाएगा कि इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कोई सूचना, जिसकी उस पर तामील की जानी अपेक्षित है, इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अनुसार समय के भीतर उस पर सम्यक् रूप से तामील हो गई है और ऐसा निर्धारिती इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में ऐसी कोई आपत्ति करने से प्रवारित होगा कि सूचना (क) उस पर तामील नहीं की गई थी; या (ख) उस पर समय के भीतर तामील नहीं की गई थी; या (ग) उसको अनुचित रीति में तामील की गई थी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

खंड 53—आय-कर अधिनियम की धारा 292ग का संशोधन करने के लिए है जो आस्तियों, लेखा बहियों आदि के बारे में उपधारणा से संबंधित है।

उक्त धारा में यह उपबंध है कि जहां कोई लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज धारा 132 के अधीन किसी तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के कब्जे में या नियंत्रण में पाई जाती है या पाई जाती हैं, वहां इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में यह उपधारणा की जा सकेगी,—

(i) ऐसी लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज ऐसे व्यक्ति की हैं या उसकी है;

(ii) ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेजों की अंतर्वस्तुएं सत्य हैं; और

(iii) हस्ताक्षर और ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेजों का प्रत्येक अन्य भाग, जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है या उसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह माना जा सकता है कि वे उसी व्यक्ति के हस्तलेख में हैं और किसी स्टांपित, निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज की दशा में यह माना जा सकेगा कि वे उस व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से स्टांपित और निष्पादित या अनुप्रमाणित किए गए थे, जिसके द्वारा उसका इस प्रकार निष्पादित या अनुप्रमाणित किया जाना तात्पर्यित है।

उक्त धारा का संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे कि, उपरोक्त उपधारणा को किसी सर्वेक्षण कार्यवाही के दौरान किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में पाए जाने वाली लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों आदि तक भी विस्तारित किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2002 से, भूतलक्षीरूप से प्रभावी होगा।

उपरोक्त उपधारणा को ऐसी लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों, या आस्तियों तक विस्तारित किए जाने का भी प्रस्ताव है जो धारा 132क के उपबंधों के अनुसार अध्यपेक्षा करने वाले अधिकारी को परिदत्त कर दिए गए हैं।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 1975 से भूतलक्षीरूप से प्रभावी होगा।

खंड 54—आय-कर अधिनियम की धारा 295 की उपधारा (2) का, उसमें एक नया खंड (चक) अंतःस्थापित करके, जो बोर्ड की नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है, संशोधन करने के लिए है जिससे बोर्ड को विनिर्दिष्ट रूप से वह प्ररूप और रीति, जिसमें प्रस्तावित धारा 195 की उपधारा (6) के अधीन किसी राशि के संदाय से संबंधित सूचना दी जा सकेगी, विहित करने की शक्ति प्रदान की जा सकेगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

खंड 55—आय-कर अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के भाग क का संशोधन करने के लिए है जो मान्यताप्राप्त भविष्य निधियों के संबंध में है।

चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 3 में यह उपबंध है कि मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी ऐसी भविष्य निधि को मान्यता दे सकेगा जो उसकी राय में नियम 4 में विहित शर्तों की और बोर्ड द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों की पूर्ति करती है।

उक्त नियम 3 के उपनियम (1) के परंतुक में यह उपबंध है कि जहां किसी भविष्य निधि को 31 मार्च, 2006 को या उसके पूर्व मान्यता प्रदान की गई है और ऐसी भविष्य निधि नियम 4 के खंड (डक) में उपवर्णित शर्तों को और ऐसी किन्हीं अन्य शर्तों को, जो बोर्ड इस निमित्त नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पूरा नहीं करती है, तो ऐसी निधि की मान्यता वापस ली जाएगी यदि ऐसी निधि 31 मार्च, 2008 को या उससे पूर्व ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करती।

उपनियम (1) के उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त समय सीमा को एक वर्ष के लिए अर्थात् 31 मार्च, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक बढ़ाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

खंड 56—धन-कर अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है जो निर्धारण से छूटे धन के संबंध में है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में एक नया परंतुक यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि निर्धारण अधिकारी ऐसे विषयों वाले शुद्ध धन से भिन्न, जो किसी अपील, निर्देश या पुनरीक्षण की विषयवस्तु हैं, शुद्ध धन का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकेगा, जो कर से प्रभार्य है और निर्धारण से छूट गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

इसके अतिरिक्त खंड 56 उक्त धारा की उपधारा (1ख) के पश्चात् एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने के लिए भी है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि, यथास्थिति, संयुक्त आयुक्त, आयुक्त या मुख्य आयुक्त के लिए, सूचना जारी करने के लिए मामले की उपयुक्तता के बारे में निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए कारणों के आधार पर समाधान हो जाने के पश्चात् स्वयं सूचना जारी करना आवश्यक नहीं है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 1998 से भूतलक्षीरूप से प्रभावी होगा।

खंड 57—धन-कर अधिनियम की धारा 17क का संशोधन करने के लिए है जो निर्धारण और पुनः निर्धारण को पूरा करने के लिए नियत समय की परिसीमा से संबंधित है।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा में नया परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां समझौता आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही का धारा 22जक के अधीन उपशमन हो जाता है वहां, यथास्थिति, निर्धारण, पुनः निर्धारण का आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी को धारा 17क में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि, धारा 22जक की उपधारा (4) के अधीन अवधि के समायोजन के पश्चात्, एक वर्ष से कम की नहीं होगी; और जहां परिसीमा की ऐसी अवधि एक वर्ष से कम की है वहां उसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से, भूतलक्षीरूप से, प्रभावी होगा।

खंड 58—धन-कर अधिनियम की धारा 18 का संशोधन करने के लिए है जो विवरणियां न देने, सूचनाओं का अनुपालन न करने, आस्तियों के छिपाने आदि के लिए शास्ति से संबंधित है।

इस धारा में एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारण या पुनः निर्धारण के किसी आदेश में किसी

निर्धारित के शुद्ध धन की संगणना करने में कोई रकम जोड़ी या अननुज्ञात की जाती है और यदि ऐसे आदेश में उपधारा (1) के अधीन शास्ति की कार्यवाहियां आरंभ किए जाने का निर्देश अंतर्विष्ट है, तो निर्धारण या पुनः निर्धारण के ऐसे आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उपधारा (1) के अधीन शास्ति कार्यवाहियां आरंभ किए जाने के लिए निर्धारण अधिकारी के समाधान का गठन करता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 1989 से, भूतलक्षी रूप से, प्रभावी होगा।

खंड 59—धन-कर अधिनियम में नई धारा 18खक अंतःस्थापित करने के लिए है जो शास्ति से उन्मुक्ति देने की आयुक्त की शक्ति से संबंधित है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि कोई व्यक्ति शास्ति से उन्मुक्ति देने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, यदि, (क) उसने धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है और धारा 22जक के अधीन समझौते की कार्यवाहियों का उपशमन हो गया है; और (ख) इस अधिनियम के अधीन शास्ति कार्यवाहियों आरंभ कर दी गई है।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उपधारा (1) के अधीन आयुक्त को आवेदन उपशमन के पश्चात् शास्ति के अधिरोपण के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि आयुक्त ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए शास्ति से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् धन-कर प्राधिकारी को उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और अपने शुद्ध धन और उस रीति का, जिसमें ऐसा शुद्ध धन व्युत्पन्न किया गया है, पूर्ण और सही प्रकटन किया है।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी व्यक्ति को उपधारा (3) के अधीन दी गई उन्मुक्ति वापस ले ली जाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, जिसके अधीन रहते हुए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी और तत्पश्चात् इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई हो।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी व्यक्ति को उपधारा (3) के अधीन दी गई उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा किसी समय वापस ली जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान धन-कर प्राधिकारी से निर्धारण के लिए सारवान किन्हीं विशिष्टियों को छिपाया था और मिथ्या साक्ष्य दिया था तथा तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसी किसी शास्ति के अधिरोपण के लिए दायी हो जाएगा, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति तब दायी होता यदि ऐसी उन्मुक्ति प्रदान न की गई होती।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

खंड 60—धन-कर अधिनियम में नई धारा 35छक अंतःस्थापित करने के लिए है जो अभियोजन से उन्मुक्ति देने की आयुक्त की शक्ति से संबंधित है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि कोई व्यक्ति अभियोजन से उन्मुक्ति देने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, यदि उसने धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है और धारा 22जक का समझौते की कार्यवाहियों का उपशमन हो गया है।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उपधारा (1) के अधीन आयुक्त को आवेदन उपशमन के पश्चात् अभियोजन कार्यवाहियों के संस्थापन के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि आयुक्त ऐसे व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, इस अधिनियम के अधीन किसी अभियोजन के अधिरोपण से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् धन-कर प्राधिकारी को उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और अपने शुद्ध धन और उस रीति का, जिसमें ऐसा शुद्ध धन व्युत्पन्न किया गया है, पूर्ण और सही प्रकटन किया है।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन 1 जून, 2007 के पूर्व किया गया है वहां आयुक्त इस अधिनियम के अधीन या

भारतीय दंड संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा किसी समय वापस ले ली जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, जिसके अधीन रहते हुए उन्मुक्ति दी गई थी और तत्पश्चात् इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई हो।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान की गई उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा किसी समय वापस ली जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् कार्यवाहियों के दौरान धन-कर प्राधिकारी से निर्धारण से सारवान किन्हीं विशिष्टियों को छिपाया था या मिथ्या साक्ष्य दिया था और तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए, जिसके संबंध में उन्मुक्ति प्रदान की गई थी या ऐसे किसी अन्य अपराध के संबंध में विचारण किया जा सकेगा, जिसके बारे में वह कार्यवाहियों के संबंध में दोषी रहा प्रतीत होता हो।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

खंड 61—धन-कर अधिनियम में नई धारा 42 अंतःस्थापित करने के लिए है जो कतिपय ऐसी परिस्थितियां अधिकथित करती है जिनमें सूचना विधिमान्य समझी जाएगी।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां कोई निर्धारित किसी निर्धारण या पुनःनिर्धारण से संबंधित किसी कार्यवाही में या जांच में उपसंज्ञात हो गया है या सहयोग कर रहा है वहां यह समझा जाएगा कि इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कोई सूचना, जिसकी उस पर तामील की जानी अपेक्षित है, इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अनुसार समय के भीतर उस पर सम्यक् रूप से तामील हो गई है और ऐसा निर्धारित इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में ऐसी कोई आपत्ति करने से प्रवारित होगा कि सूचना (क) उस पर तामील नहीं की गई थी; या (ख) उस पर समय के भीतर तामील नहीं की गई थी; या (ग) उस पर अनुचित तरीके से तामील की गई थी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

खंड 62—धन-कर अधिनियम की धारा 42घ का संशोधन करने के लिए है जो आस्तियों, लेखा बहियों आदि के बारे में उपधारणा से सम्बन्धित है।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि जहां कोई लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज धारा 37क के अधीन किसी तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के कब्जे में या नियंत्रण में पाई जाती हैं या पाई जाती हैं, वहां इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में यह उपधारणा की जाएगी कि —

(i) ऐसी लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज उस व्यक्ति की है या हैं;

(ii) ऐसी लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की अंतर्वस्तुएं सत्य हैं; और

(iii) ऐसी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और उनका प्रत्येक अन्य भाग जिनका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है या उनके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह उपधारणा की जा सकेगी कि वे किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हैं या उसके हस्तलेख में हैं और स्टांपित, निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज की दशा में यह उपधारणा की जाएगी कि वह उस व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से स्टांपित और निष्पादित या अनुप्रमाणित की गई थी जिसके द्वारा इस प्रकार निष्पादित या अनुप्रमाणित किया जाना तात्पर्यित है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे ऊपर वर्णित उपधारणा को ऐसी लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या आस्तियों तक विस्तारित किया जा सके जो धारा 37ख के उपबंधों के अनुसार अध्यापेक्षा करने वाले अधिकारी को परिदत्त की गई हैं।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 1975 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

सीमाशुल्क

खंड 63—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ख का संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को किसी व्यक्ति द्वारा किसी माल पर निर्धारित या अवधारित या संदत्त शुल्क से अधिक सीमाशुल्क के रूप में संगृहीत की गई किसी रकम का संग्रहण करने के लिए और किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे किसी माल पर, जो शुल्क से पूर्णतया छूट प्राप्त है या शून्य दर पर प्रभार्य है, सीमाशुल्क के रूप में संगृहीत किसी रकम का संग्रहण करने के लिए भी समर्थ बनाने हेतु उसमें नई उपधारा अंतःस्थापित की जा सके। तदनुसार उक्त धारा की उपधारा (2) और उपधारा (4) में कतिपय पारिणामिक संशोधन किए गए हैं।

खंड 64—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 108 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि सभी सीमाशुल्क अधिकारियों को समन जारी करने की शक्तियां प्रदान करने की दृष्टि से, उक्त धारा की उपधारा (1) से “केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से सशक्त किए गए” शब्दों का लोप किया जा सके।

खंड 65—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 117 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए शास्ति की अधिकतम रकम को, जहां अन्यत्र कोई अभिव्यक्त शास्ति उपबंधित नहीं है, विद्यमान दस हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए किया जा सके।

खंड 66—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129क की उपधारा (2) का, एक परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि सीमाशुल्क के आयुक्तों की समिति की राय आयुक्त (अपील) द्वारा अपील में पारित आदेश से भिन्न है, तो वह उस मामले को अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त को निर्देश करेगी, जो मामले के तथ्यों और भिन्नता के प्रश्नों पर विचार करेगा और यदि उसकी यह राय है कि आयुक्त (अपील) द्वारा दिया गया आदेश वैध या उचित नहीं है तो समुचित अधिकारी को आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करने का निर्देश देगा। अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त, उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी पर अधिकारिता रखने वाला सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त होगा, जिसने मामले का विनिश्चय किया है।

खंड 67—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129घ का इस दृष्टि से संशोधन करने के लिए है कि —

(i) उपधारा (1) में, एक परंतुक अंतःस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि सीमाशुल्क के मुख्य आयुक्तों की समिति की राय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के रूप में सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में भिन्न है, तो वह मामले को बोर्ड को निर्देश करेगी, जो मामले के तथ्यों और उनके बीच भिन्नता पर विचार करेगा और यदि उसकी यह राय है कि आयुक्त द्वारा दिया गया आदेश वैध या उचित नहीं है तो वह आयुक्त या किसी अन्य आयुक्त को आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में आवेदन करने का निर्देश देगा ;

(ii) उपधारा (3) का यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापन किया जाए कि अधिनियम की धारा 129घ की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आदेश न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन उक्त अधिनियम की धारा 129घ की उपधारा (1) में संशोधन की दृष्टि से पारिणामिक प्रकृति का है।

खंड 68—सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 129ड अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि, जब विनिश्चय अपीलार्थी के पक्ष में हो, तब आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण के आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा जमा की गई रकम के विलंबित प्रतिदाय की दशा में ब्याज के संदाय के लिए उपबंध किया जा सके। इसमें यह उपबंध है कि यदि अपील प्राधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर रकम का प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो जब तक अपील प्राधिकारी के आदेश पर उच्चतर न्यायालय या अधिकरण द्वारा रोक नहीं लगा दी जाती है, अपील प्राधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् उस रकम के प्रतिदाय की तारीख तक धारा 27क में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज का संदाय किया जाएगा।

खंड 69—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 141 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि उस रीति को विनियमित किया जा सके, जिसमें आयातित या निर्यात माल को किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त, भंडारित, परिदत्त, प्रेषित किया जा सकेगा या अन्यथा संभाला जा सकेगा और पूर्वोक्त क्रियाकलापों में लगे व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके।

खंड 70—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 158 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि किसी नियम के उल्लंघन के लिए शास्ति की अधिकतम रकम को पांच सौ रुपए से बढ़ाकर पचास हजार रुपए और विनियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति की अधिकतम रकम को भी दो सौ रुपए से बढ़ाकर पचास हजार रुपए किया जा सके।

खंड 71—सा0का0नि0 673(अ), तारीख 17 नवंबर, 2005 (97/2005-सीमाशुल्क) द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 277(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2003 (53/2003-सीमाशुल्क) की शर्त सं0 7 को भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए है जिससे आयातकर्ता को शुल्क मुक्त प्रत्यय हकदारी (डीएफसीई) प्रमाणपत्र में विकलित की गई रकम के लिए अतिरिक्त शुल्क की वापसी या केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके।

सीमाशुल्क टैरिफ

खंड 72—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की,—

(i) पहली अनुसूची का कतिपय मदों पर शुल्क की दर बढ़ाने की दृष्टि से दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है ;

(ii) दूसरी अनुसूची का, क्रोमियम, अयस्क और सांघ्र पर निर्यात शुल्क बढ़ाने की दृष्टि से तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन करने के लिए है।